

दिल्ली नगर निगम द्वारा संपत्ति कर के मूल्यांकन के लिये मानवांड

1227. श्री चन्द्र पाल शैलानी : क्या गृह मंदी यह बताने की हुपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम द्वारा किस भाषार पर संपत्ति कर का मूल्यांकन किया जाता है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल में कर योग्य मूल्य में वृद्धि न करने के बारे में कोई कैसला दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके कार्यान्वयन के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या समान "कवड़ एरिया" वाले मकानों के लिये अलग-अलग कर योग्य मूल्य हो सकता है; और

(ङ) क्या केवल एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के परिणामस्वरूप कर योग्य मूल्य 380/-रुपये से बढ़ाकर 1080/-रुपये किया जा सकता है?

गृह मंदालय में राज्य मंदी (अंग्रेजी महानगर) :
(क) से (ग). तक:—

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि निगम द्वारा दिल्ली नगर पालिका अधिनियम, 1957 की धारा 116 के परन्तुक के अनुसार निकाले गये कर योग्य मूल्य के आधार पर संपत्ति कर का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि संपत्ति कर के लिए मूल्यांकन योग्य किसी भूमि अथवा भवन का कर योग्य मूल्य वह वार्षिक किराया होगा, जिस पर ऐसी भूमि अथवा भवनों को मरम्मत आदि के सिए 10% घटाकर वर्ष दर वर्ष यथोचित किराये पर दिये जाने की आशा की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने हाल के एक निर्णय में यह निर्धारित किया है कि किसी संपत्ति का यथोचित किराया मूल्य दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम के परन्तुकों के संदर्भ में ही निर्धारित किया जा सकता है। निगम द्वारा न्यायालय के इस निर्णय को कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(घ) तथा (ङ). दिल्ली नगर निगम के अनुसार समान कवड़ एरिया वाले मकानों के लिए नियन्त्रित कर योग्य मूल्य हो सकता है और केवल एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के परिणामस्वरूप कर योग्य मूल्य में वृद्धि की जा सकती है जो अत्येक मामले के गुण दौष पर निर्भर होगा।

दिल्ली प्रशासन की वरीयता सूची में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के नाम शामिल किया जाता

1228. श्री चन्द्र पाल शैलानी : क्या गृह मंदी यह बताने की हुपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के नाम योग्यता के अनुसार उनके अपने प्रेड की वरीयता सूची में शामिल नहीं किये गये हैं अपितु उनके नाम सूची के अन्त में रखे गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) योग्यता के अनुसार वरीयता सूची में उनके नाम शामिल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि उनके साथ न्याय किया जा सके ?

गृह मंदालय में राज्य मंदी (श्री योगेन्द्र मकानाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान। जैसा दिल्ली प्रशासन द्वारा बताया गया है, अधिकारियों को वरीयता देने से संबंधित नियमों का पूरी तरह पालन किया जाता है। इस समय प्रशासन द्वारा अपनाये गये नियमों के दो सेट हैं अर्थात् क्वालिफाइंग सर्विस की लंबाई के अनुसार किसी प्रेड में अधिकारियों की वरीयता निर्धारित करने के दिल्ली राज्य सेवा (वरीयता) नियम, 1954 और दिल्ली प्रशासन सेवा (वरीयता) नियम, 1965 जिसमें चयन बोर्ड अधिवायिक प्रोफ्रेशनल समिति द्वारा उनको दिये गये गुणदोष के अनुसार अधिकारियों की वरीयता निर्धारित करने की व्यवस्था है। किसी विशेष प्रेड में चयन करने के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण से संबंधित तत्संबंधी अनुदेशों पर उचित व्यापार दिया जाता है और एक बार चयन हो जाने पर सामान्य और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों दोनों उम्मीदवारों को वरीयता सूची में उनके पारस्परिक गुण-दोष के क्रम में रखा जाता है।

(ख) तथा (ग); प्रश्न नहीं उठता।

Representations from SC/ST Stenographers/Head Clerks in Delhi Administration

1229. SHRI CHANDRA PAL SHAILANI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether some SC/ST stenographers/Head Clerks working in Delhi Administration have been representing